भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 322

(जिसका उत्तर सोमवार, 05 फरवरी, 2024/16 माघ, 1945 (शक) को दिया जाना है)

भारत की ऋणग्रस्तता के बारे में अनुमान

322. श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डी:

श्री रघु राम कृष्ण राजू:

क्या **वित्त मंत्रा** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) सहित विभिन्न एजेंसियों द्वारा परिदृश्य-आधारित आकलन से भारत की ऋणग्रस्तता के स्तरों के बारे में किए जा रहे कतिपय तथ्यात्मक रूप से गलत अनुमानों को दूर किया है, जिसमें चेतावनी दी गई थी कि प्रतिकूल परिस्थितियों में सरकारी ऋण 2027-28 तक सकल घरेलू उत्पाद का 100 प्रतिशत तक पहुंच सकता है। क्योंकि संभावित परिदृश्यों को ध्यान में रखते हुए कतिपय अनुमान लगाए गए हैं जो तथ्यात्मक स्थिति को नहीं दर्शाते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि रिपोर्ट की यह ऐसी किसी व्याख्या, जिसका आशय यह है कि सामान्य सरकारी ऋण 100 प्रतिशत से अधिक पहुच जाएगा, गलत है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा क्या अब तक क्या परिणामों प्राप्त हुए हैं?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

जी, हां।

(क) और (ख): सरकार ने दिनांक 22 दिसंबर, 2023 की प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से स्पष्ट किया है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट में संभावित परिदृश्यों को ध्यान में रखते हुए कुछ अनुमान लगाए गए हैं जो तथ्यात्मक स्थिति को नहीं दर्शाते हैं। आईएमएफ की रिपोर्ट में केवल सबसे खराब स्थिति की बात की गई है जो कि सिद्ध तथ्य नहीं है। आईएमएफ की वही रिपोर्ट यह भी इंगित करती है कि अनुकूल परिस्थितियों में, जीडीपी अनुपात में सामान्य सरकारी ऋण उसी अवधि में 70 प्रतिशत से नीचे गिर सकता है जिसमें इसे बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। इसलिए, रिपोर्ट में की गई किसी भी व्याख्या का अर्थ है कि सामान्य सरकारी ऋण मध्यम अवधि में सकल घरेलू उत्पाद के 100 प्रतिशत से अधिक होगा, जो कि गलत है। सरकार द्वारा किए गए राजकोषीय समेकन उपायों जिनमें राजकोषीय अनुशासन, संसाधनों का बेहतर संग्रहण और व्यय की गुणवत्ता में सुधार करना शामिल है, के परिणामस्वरूप ऋण और जीडीपी अनुपात कम हो रहा है। परिणामस्वरूप, वित्त वर्ष 2023-24 का संशोधित अनुमान राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 5.8 प्रतिशत पर इंगित करता है, जो वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट अनुमान में सकल घरेलू उत्पाद के 5.1 प्रतिशत तक और कम होने का अनुमान है। सामान्य सरकारी ऋण भी वित्त वर्ष 2020-21 में लगभग 88 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में लगभग 81 प्रतिशत हो गया है।

****